आय-कर संदर्भ।

माननीय न्यायालय शमशेर बहादुर और आर. एस. नरूला, जे. जे.

डालमिया दादरी सीमेंट, लिमिटेड,-याचिकाकर्ता

बनाम

आयुक्त, आय-कर,-प्रत्यर्थी

आयकर संदर्भ सं1965 का 61

6 मार्च, 1969

आय-कर अधिनियम (1922 का 11)-धारा 10 (2) (15)निर्धारिती एक ऐसी कंपनी है जिसके पास एक निश्चित अवधि के लिए प्रबंध एजेंसी है-मुआवजे के रूप में एकमुश्त राशि के भुगतान पर एजेंसी की समयपूर्व समाप्ति-ऐसी राशि का भुगतान-चाहे वह राजस्व की प्रकृति में हो या पूंजीगत व्यय-ऐसा भुगतान-चाहे निर्धारिती कंपनी के हाथों में अनुमेय कटौती हो।

माना जाता है कि पूंजी और राजस्व व्यय की अवधारणाओं को आयकर अधिनियम, 1922 में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। जब निर्धारिती कंपनियों द्वारा आर्थिक या प्रबंधकीय संकट के दबाव में एकमुश्त राशि के भुगतान पर निश्चित अवधि के लिए प्रबंध एजेंसी की पूर्व-परिपक्वता समाप्ति के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं और भविष्य की आर्थिक समृद्धि की नींव या आधार रखने के लिए नियोजित नीति के माध्यम से नहीं, तो एजेंसी के नुकसान के मुआवजे के रूप में एक कंपनी द्वारा एकमुश्त भुगतान किया जाता है, जिससे कंपनी राजस्व खातों के लिए देय कमीशन के भविष्य के वार्षिक भुगतान से खुद को मुक्त करती है, राजस्व व्यय के रूप में उचित रूप से कटौती योग्य है। लेकिन जहां निर्धारिती कंपनी को न तो किसी तत्काल या वर्तमान खतरे का सामना करना पड़ता है और न ही प्रबंधन एजेंसी को समाप्त करने के लिए कंपनी को किसी वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है, एकमुश्त राशि का भुगतान निर्धारिती कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से एक स्थायी लाभ में परिणाम देता है। कंपनी उन प्रबंध एजेंटों के समेकित दावे को जोड़ती है जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। यदि जो समझौता समाप्त किया जा रहा है वह समनुदेश्य है और कोई उत्तराधिकारी प्रबंध अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जाता है, तो स्थायी प्रकृति का एक स्पष्ट लाभ अस्तित्व में लाया जाता है, जो निर्धारिती कंपनी के लिए सामग्री या अचल संपत्ति से अप्रभेद्य लाभ है। ऐसे मामलों में निर्धारिती कंपनी द्वारा अपनी एक निश्चित अवधि की प्रबंध अभिकरण की समयपूर्व समाप्ति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान पूंजीगत व्यय है और यह निर्धारिती कंपनी के हाथों में आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 (2) (xv) के तहत अनुमेय कटौती नहीं है।

(Paras 8, 10, 17 & 24)

आयकर अपीलीय अधिकरण (दिल्ली न्यायपीठ 'क') द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66 की उपधारा 1 के अधीन निम्नलिखित प्रश्न पर राय के लिए इस न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया मामला। (Regarding Assessment year 1953-54).

"क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, रुपये का भुगतान। निर्धारिती कंपनी के हाथों में आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 (2) (xv) के तहत 6 लाख रुपये की कटौती स्वीकार्य नहीं थी।"

याचिकाकर्ता के लिए जी. सी. शर्मा और एन. एन. गोस्वामी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी के लिए डी. एन. अवस्थी, और बी. एस. गुप्ता, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय

शमशेर बहादुर, जे।

1) यह भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन इस न्यायालय के लिए एक आय-कर संदर्भ है, जिसे निर्धारिती कंपनी, डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, जिसे इसके पश्चात् कंपनी भी कहा जाता है, के कहने पर अधिनियम कहा जाता है।

2) 26 मई, 1938 से, जब निर्धारिती कंपनी पंजीकृत थी, इसने डालमिया जैन एंड कंपनी को 30 वर्षों की अवधि के लिए अपने प्रबंध एजेंटों के रूप में नियुक्त किया। कंपनी के शुद्ध वार्षिक लाभ पर दस प्रतिशत कमीशन के अलावा 1,000 प्रति माह। प्रबंध अभिकर्ताओं के पास इस समझौते के तहत अपने अधिकार किसी भी निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को कुछ प्रतिबंधों के अधीन सौंपने की शक्ति थी, जिनसे हम संबंधित नहीं हैं। कंपनी और प्रबंध अभिकर्ताओं के बीच विवादों का निपटारा मध्यस्थता के संदर्भ में किया जाना था। इसके बाद 14 अगस्त, 1941 को। डालमिया जैन एंड कंपनी (जींद स्टेट) लिमिटेड को 25 मई, 1968 को समाप्त होने वाले तीस साल के कार्यकाल के अवशेष के लिए समान नियमों और शर्तों के तहत डालमिया जैन एंड कंपनी के बजाय प्रबंध एजेंट नियुक्त किया गया था।

3) कंपनी के निदेशक मंडल ने 14 नवंबर, 1952 को प्रबंध एजेंसी समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया और 2 दिसंबर, 1952 को शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रबंध अभिकर्ताओं ने 3 दिसंबर, 1952 को प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद वापस लिखा कि प्रस्ताव ने प्रबंध एजेंसी के अनुबंध का उल्लंघन किया है और 5 करोड़ रुपये का दावा दायर किया है। 8,87,800 मुआवजे के रूप में, जिसमें से 8,22,168 रुपये समझौते की समय से पहले समाप्ति के लिए थे, जो अगले 15 वर्षों और 178 दिनों के लिए अस्तित्व में था, राशि की गणना पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित औसत कमीशन के 61 गुना पर की जा रही थी। रुपये की तुलनात्मक रूप से छोटी शेष राशि। 65,687-10-9 रुपये के मासिक पारिश्रमिक के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में दावा किया गया था। 61 वर्ष की अवधि के लिए 1,000। कंपनी के निदेशक मंडल ने 9 दिसंबर को स्थिति पर विचार करने के लिए बैठक की। 1952 में, श्री एस. के. सांघी को प्रबंध एजेंसी के साथ दावे का निपटान करने के लिए एक निदेशक के रूप में अधिकृत किया गया और उन्होंने बोर्ड द्वारा रुपये की राशि की स्वीकृति के लिए फिर से सिफारिश की। 6,00,000 जिस पर मामला सुलझाया जा सका। बोर्ड ने 12 दिसंबर, 1952 को श्री संघी के इस सुझाव को मंजूरी दी और 30 दिसंबर, 1952 को कंपनी की असाधारण आम बैठक द्वारा पारित एक अन्य प्रस्ताव के अनुसरण में, 6,00,000 रुपये की राशि वास्तव में उसी दिन प्रबंध एजेंसी को दी गई थी। समय के साथ निर्धारण वर्ष 1953-54 के संबंध में यह प्रश्न उठा कि क्या रु. 6,00,000 उन भत्तों से संबंधित अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (xv) के अधीन आता है जिनकी लाभों की संगणना में कटौती की जानी है, अर्थात् –

"(xv) कोई भी व्यय जो खंड (i) से (xiv) में वर्णित प्रकृति का भत्ता नहीं है, समावेशी है और निर्धारिती के पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति में नहीं है, जो पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारिती के लिए निर्धारित या व्यय किया गया है। ऐसे व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय का उद्देश्य।"

निर्धारिती कंपनी का मामला है और हमेशा से रहा है कि रु। 6,00,000 का व्यय व्यापार के प्रयोजनों के लिए किया गया था और 'पूंजीगत व्यय की प्रकृति में' नहीं होने के कारण सामान्य व्यापारिक व्यय के रूप में कटौती योग्य था।

4) आयकर अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि सेठ राम किशन डालमिया, जिनके पास निर्धारिती कंपनी का नियंत्रण था और प्रबंध एजेंसी के पास 5,000 शेयरों में से 4,900 शेयर थे, के बीच हितों की एक आवश्यक एकता थी और 6,00,000 रुपये का भुगतान कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए एक प्रामाणिक लेनदेन का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। आयकर अधिकारी के अनुसार, पूरे मामले की इतनी जल्दबाजी में योजना बनाई गई थी कि पूर्व नियोजित छलावरण का आदेश दिया जा सके। प्रबंध अभिकर्ताओं को दी जाने वाली 6,00,000 रुपये की राशि एक प्रकार की सहायता राशि थी जो राजस्व व्यापार व्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं थी। यह कि 6,00,000 रुपये की प्राप्ति के तुरंत बाद 27 अप्रैल, 1953 को प्रबंध अभिकर्ता परिसमापन में चले गए, निर्धारण प्राधिकरण की राय में उसी दिशा में एक सूचक था, जिसने तदनुसार कंपनी के दावे को अस्वीकार कर दिया।

5) अपीलीय सहायक आयुक्त ने लेन-देन के बारे में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और 1952 से पहले के तीन वर्षों के लिए पर्याप्त लाभ और पूर्वगामी सोलह वर्षों के कमीशन में शामिल वित्तीय बलिदान को ध्यान में रखते हुए पाया कि 6,00,000 रुपये की राशि अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के तहत कटौती योग्य राजस्व व्यय थी। अपीलीय अधिकरण को एक और अपील में अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा किए गए लेन-देन की प्रामाणिक प्रकृति के संबंध में निष्कर्ष की पुष्टि की गई, हालांकि राजस्व की ओर से इसे एक मजबूत चुनौती दी गई थी। हमले की विस्तृत जांच के बाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा -

"इन परिस्थितियों में हमारा मानना है कि यह व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया गया था और राजस्व के खिलाफ पहले मुद्दे का जवाब देता है।"

इस परिणाम तक पहुँचने में कि 6,00,000 रुपये के भुगतान द्वारा निपटान व्यावसायिक विचार और वाणिज्यिक समीचीनता के लिए था, अधिकरण ने उस राशि को गणना में लिया जिसे कंपनी स्थायी रूप से प्रबंध एजेंटों से छुटकारा पाकर बचा रही थी। यह आम बात है कि जिन प्रबंध एजेंटों की एजेंसी को 1952 में समाप्त कर दिया गया था, उनके स्थान पर कोई प्रबंध एजेंट नियुक्त नहीं किया गया था।

6) दूसरे मुद्दे के संबंध में कि क्या प्रबंध अभिकर्ताओं को 6,00,000 रुपये का भुगतान 'पूंजीगत व्यय की प्रकृति में' था, अधिकरण ने विचार किया कि कंपनी को जो लाभ प्राप्त हुआ था वह इस प्रकार की स्थायी प्रकृति का था कि वह पूंजीगत व्यय के बराबर था।

7) 1 नवंबर, 1962 को पारित न्यायाधिकरण के आदेश को इस संदर्भ में चुनौती देने की मांग की गई है, जो न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत मामले के बयान के अनुसार, हमारी राय के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठाता है -

"क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, रुपये का भुगतान। निर्धारिती कंपनी के हाथों में आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 (2) (xv) के तहत 6 लाख रुपये की कटौती स्वीकार्य नहीं थी।

प्रश्न का ढांचा स्पष्ट रूप से लेन-देन की प्रकृति के बारे में तथ्य के प्रश्न को फिर से बड़े पैमाने पर रखता है। श्री जी. सी. शर्मा ने अपने अत्यंत सक्षम और सशक्त तर्क में दृढ़ता से तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय को इस विवाद में फिर से प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। श्री शर्मा के तर्क की दृढ़ता को उच्चतम न्यायालय के हाल के दो फैसलों से बल मिलता है। आयकर आयुक्त, बंबई उत्तर बनाम चंदूलाल केशवलाल और कंपनी (1) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलीय अधिकरण ने यह पाया है कि अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के अधीन वाणिज्यिक समीचीनता के कारणों से किसी वस्तु की कटौती की जा सकती है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है कि क्या व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारिती के व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य से किया गया था। मामले के इस पहलू पर उच्चतम न्यायालय का बाद का निर्णय आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी बनाम ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड (2) है, जहां यह देखा गया था कि यह प्रश्न कि क्या कोई निश्चित व्यय निर्धारिती के कार्य के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से या विशेष रूप से निर्धारित किया गया था या लंबित था, एक ऐसा प्रश्न है जिसमें, पहली जगह, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा तथ्यों का निर्धारण और दूसरी जगह, इस तरह पाए गए तथ्यों के लिए कानून के सही सिद्धांत का अनुप्रयोग शामिल है। इसलिए, यह सवाल तथ्य और कानून का एक मिश्रित सवाल है। वह मामला एक प्रबंध एजेंसी की समाप्ति और उसके बदले भुगतान किए गए मुआवजे से भी संबंधित था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह प्रश्न कि क्या निर्धारिती कंपनी द्वारा प्रबंध अभिकरण समझौते की समाप्ति प्रामाणिक नहीं थी और यह एक अप्रत्यक्ष या अनुचित उद्देश्य के लिए किया गया था, अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न था और उच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकरण के समक्ष साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन शुरू करने और इस तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि प्रबंध अभिकरण समझौते की समाप्ति एक प्रामाणिक लेन-देन नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को विक्षिप्त कर दिया था, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उस मामले में संदर्भ आयकर आयुक्त के कहने पर दिया गया था। वर्तमान मामले में, हम संतुष्ट हैं कि अपीलीय अधिकरण द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित है और इसके अलावा कि राजस्व ने निष्कर्ष की वैधता को चुनौती देने के लिए संदर्भ के लिए कभी नहीं कहा है, इस स्तर पर तथ्य के प्रश्न को उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। संदर्भ में बचा हुआ प्रश्न वह है जो पूंजी और राजस्व व्यय के बीच परिसीमन की रेखा से संबंधित न्यायालयों में अक्सर उठा है और जिस पर दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा विस्तृत तर्कों को संबोधित किया गया है।

8) पूंजी और राजस्व व्यय की अवधारणाओं को कानून में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इंग्लैंड और भारत दोनों में रिपोर्ट किए गए निर्णयों में प्रतिष्ठित न्यायाधीशों द्वारा इंगित दिशानिर्देशों की कोई कमी नहीं है। मैं शुरू में पेज 488 पर डोवेव बनाम जॉन कोरी (3) में लॉर्ड मैकनाघटेन द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता -
उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि किसी भी न्यायाधिकरण के लिए यह वांछनीय है कि वह ऐसा करे जिसे करने से संसद को रोका गया है-यानी व्यावसायिक मामलों के संचालन में व्यापारियों के मार्गदर्शन या शर्मिंदगी के लिए सटीक नियम तैयार करना। अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किसी विशेष मामले से निपटने में कभी भी ज्यादा कठिनाई नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि कभी भी नहीं होगी, और अपने लिए बोलते हुए, मुझे अधिक करने का प्रयास करने के विवेक पर संदेह है।"

9) दृढ़ संकल्प का प्रश्न दो स्थितियों में उत्पन्न होता है। ऐसा कभी-कभी होता है जब एक करदाता अपने लाभ की गणना में स्वीकार्य कटौती के बीच संवितरण की एक निश्चित वस्तु को शामिल करने का दावा करता है। ऐसे मामलों में, जैसा कि वर्तमान में है, सवाल यह है कि क्या व्यय पूंजी या राजस्व प्रकृति का है। राजस्व ऐसे मामलों में स्थिति लेता है कि व्यय पूंजीगत प्रकृति का हो। मामलों के अन्य समूह में, यह प्राप्तकर्ता निर्धारिती है जो दावा करता है कि वस्तु पूंजीगत प्रकृति की है और इस प्रकार आय-कर के लिए आकलन योग्य नहीं है। स्वाभाविक रूप से, राजस्व यह स्थिति लेता है कि वस्तु एक राजस्व रसीद का

गठन करती है। यह नियंत्रित करने के लिए सिद्धांत कि क्या प्राप्त भुगतान पूंजी या राजस्व प्राप्ति की प्रकृति का है या क्या किया गया व्यय पूंजी या राजस्व प्रकृति का है, सामान्य हैं। जैसा कि कंगा और पालखीवाला ने "द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम-टैक्स"-छठे संस्करण (खंड I) में पृष्ठ 434 पर कहा है –

"आम तौर पर, पूंजीगत प्राप्तियों और आय प्राप्तियों और आय प्राप्तियों के बीच अंतर करने में जिन मानदंडों का उपयोग किया जाता है, वे पूंजीगत संवितरण और राजस्व संवितरण के बीच अंतर करने का भी काम करेंगे।"

10) ऐसे कई मानदंड या परीक्षण हैं जिन्हें न्यायालयों द्वारा अपनाया गया है, लेकिन जो सबसे व्यापक रूप से और आमतौर पर अपनाए जाते हैं, वे दो अंग्रेजी निर्णयों में निहित होते हैं और जहां तक मामले का संबंध है, एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। स्कॉटिश कोर्ट ऑफ सेशन के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड डुनेडिन ने पृष्ठ 536 पर वल्लाम्ब्रोसा रबर कंपनी लिमिटेड बनाम किसान (सर्वेक्षक या कर) (4) के मामले में यह कहा -

"अब, मैं यह नहीं कहता कि यह विचार पूरी तरह से अंतिम या निर्धारक है, लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि यह एक बुरा मानदंड नहीं है कि पूंजीगत व्यय क्या है जबकि आय व्यय क्या है, यह कहना कि पूंजीगत व्यय एक ऐसी चीज है जो एक बार और हमेशा के लिए खर्च होने वाली है, और आय व्यय एक ऐसी चीज है जो हर साल दोहराने वाली है।"
इस मानदंड के परिप्रेक्ष्य में देखने पर लगता है कि एकमुश्त के रूप में 6,00,000 रुपये का भुगतान पूंजीगत व्यय के बराबर होगा। हालांकि, अब यह आम तौर पर समझा जाता है कि इस परेशान करने वाले प्रश्न का उत्तर देने में एकमुश्त भुगतान का कोई महत्व नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, एकमुश्त और आवधिक राशि के बीच अंतर में कोई जादू नहीं है। एकमुश्त भुगतान एक राजस्व व्यय हो सकता है जब यह वार्षिक राजस्व किराया भुगतान की एक श्रृंखला की गणना का प्रतिनिधित्व करता है और एक आवर्ती आवधिक भुगतान पूंजीगत व्यय हो सकता है जब यह पूंजीगत राशि की किश्तों के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है।

11) प्रस्तुत दूसरा परीक्षण ब्रिटिश इंसुलेटेड एंड बेल्सबी केबल्स लिमिटेड बनाम एथर्टन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय है। (5). उस मामले में निर्धारिती कंपनी ने अपनी शक्तियों के तहत अपने लिपिक और तकनीकी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन निधि की स्थापना की। लाभार्थियों और कंपनी दोनों ने इस कोष में योगदान दिया। कंपनी द्वारा इस निधि के लिए वर्तमान लाभों में से £31,784 की राशि अलग रखी गई थी और संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए अपने लाभों को जमा करने में स्वीकार्य कटौती के रूप में दावा किया गया था। विस्कॉन्ट गुफा L.C. के दावे को अस्वीकार करते हुए। पृष्ठ 213 में इस प्रकार कहा गया है-"लेकिन जब कोई व्यय न केवल एक बार और हमेशा के लिए किया जाता है, बल्कि किसी व्यापार के स्थायी लाभ के लिए किसी संपत्ति या लाभ को अस्तित्व में लाने की दृष्टि से किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के व्यय को उचित रूप से राजस्व के लिए नहीं बल्कि पूंजी के लिए जिम्मेदार नहीं मानने के लिए बहुत अच्छा कारण है (विपरीत निष्कर्ष की ओर ले जाने वाली विशेष परिस्थितियों के अभाव में)।

इस प्रकार उस कसौटी को जोड़ा गया जिसे लार्ड डुनेडिन ने वल्लाम्ब्रोसा के मामले में अपनाया था। (4). न केवल एक बार और हमेशा के लिए भुगतान किए जाने के अलावा, व्यय को एक व्यापार के स्थायी लाभ के लिए एक संपत्ति या लाभ को अस्तित्व में लाना था। लॉर्ड केव की राय में, कंपनी द्वारा पेंशन निधि में भुगतान पूंजीगत व्यय की प्रकृति में था क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति लेकर आया जिसके कारण एक संतुष्ट और कुशल कर्मचारी बने, जो स्थायी प्रकृति का लाभ था। बहुमत की राय रखने वाले लॉर्ड एटकिंसन ने पृष्ठ 222 पर कहा -

उन्होंने कहा, "अगर इस संबंध में इस्तेमाल किया गया 'परिसंपत्ति' शब्द किसी भौतिक चीज तक सीमित है- और मुझे नहीं लगता कि इसे इतना सीमित किया जा सकता है-तो मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर इस पेंशन कोष के अस्तित्व के परिणामस्वरूप कंपनी के कर्मचारी अधिक विवादित हो जाते हैं और अपनी सेवा बदलने के लिए कम इच्छुक होते हैं। इसलिए, कुल मिलाकर, अधिक कुशल, ये परिणाम जब सुरक्षित होते हैं तो एक के बराबर होते हैं।"

निर्धारिती कंपनी की ओर से तर्क उसके प्रमुख समर्थन के लिए रॉलेट, जे. द्वारा एक निर्णय पर निर्भर करता है, जिसे अपील न्यायालय द्वारा एंग्लो-फारसी ऑयल कंपनी लिमिटेड बनाम डेल में पुष्टि की गई है। (6). अपीलार्थी एंग्लो-फारसी ऑयल कंपनी ने फारस और पूर्व में तेल और पेट्रोलियम की बिक्री के लिए एक प्रबंध एजेंसी समझौते को निष्पादित किया। एजेंटों को प्रिंसिपल के व्यवसाय का प्रबंधन करना था और अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करना था और उन्हें अपनी सेवाओं के बदले कमीशन की एक श्रृंखला प्राप्त करनी थी जो कंपनी के व्यवसाय के विकास के साथ एक बहुत बड़ी राशि में बदल गई। कंपनी और प्रबंध एजेंटों के बीच एक व्यवस्था की गई थी, जिनके पास अभी भी चलने के लिए कई साल थे, £3,00,000 की एकमुश्त भुगतान के लिए उनकी सेवाओं की समाप्ति के लिए। जो कमीशन वास्तव में अर्जित किया जा रहा था, वह लगभग 100,000 पाउंड के आसपास पहुंच गया था। एजेंटों को स्वैच्छिक परिसमापन में जाना था और कंपनी को एजेंटों के कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में लेना था, जहां तक उन कर्मचारियों को उनके पास आने की परवाह थी, लेकिन एजेंट कर्मचारियों पर आने के लिए कोई दबाव डालने के लिए सहमत नहीं थे। कंपनी द्वारा भुगतान किए गए £3,00,000 की राशि को लाभ की गणना से निकालने की मांग की गई थी और न्यायमूर्ति रॉलेट ने कहा कि ऊपर उल्लिखित परीक्षण में लॉर्ड केव का अर्थ है कि जो लाभ रहता है वह इस तरह से होना चाहिए कि निश्चित पूंजी बनी रहे। यदि मैं ऐसा कहता हूं, तो लॉर्ड केव के परीक्षण के लिए रॉलेट, जे. के 'विवरण' को अपील न्यायालय की मंजूरी मिल गई। लॉरेंस, L.J. ने पृष्ठ 269 पर कहा -

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य परिस्थितियों में जहां कोई व्यापारी अपने कार्य व्यय में बचत करने के लिए किसी विशेष अभिकर्ता या नौकर की सेवा प्रदान करता है और अभिकरण या सेवा समझौते को रद्द करने के लिए भुगतान करता है, जैसे कि भुगतान राजस्व के लिए उचित रूप से प्रभार्य है; इसमें निश्चित पूंजी में कोई वृद्धि या निकासी शामिल नहीं है; यह विशुद्ध रूप से एक कार्य व्यय है।"

यह स्वीकार करते हुए कि फारस में कंपनी के व्यवसाय को चलाने के तरीके में बदलाव के परिणामस्वरूप, वास्तव में, कंपनी के व्यापार का अधिक किफायती और कुशल संचालन हुआ था, लॉर्ड जस्टिस ने कहा कि हालांकि इस अर्थ में यह कंपनी के व्यवसाय के लिए फायदेमंद साबित हुआ था, 'यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के बदलाव लाने में खर्च ने कंपनी के व्यापार के स्थायी लाभ के लिए एक लाभ पैदा किया है'। लॉर्ड जस्टिस रोमर ने इन शब्दों में ट्रायल जज के दृष्टिकोण का समर्थन किया-"मैं मिस्टर जस्टिस रॉलेट से सहमत हूं कि 'स्थायी' का अर्थ है 'स्थायी पूंजी के तरीके में स्थायी'। यह एक ऐसी संपत्ति प्राप्त करने की दृष्टि से बनाया गया है जिसे व्यापार के दौरान अपेक्षाकृत कम समय में वापस किया जा सकता है। न ही, निश्चित रूप से, लाभ एक सकारात्मक चरित्र का होना चाहिए। लाभ में एक निश्चित पूंजी की वस्तु से छुटकारा पाना शामिल हो सकता है जो एक भारी चरित्र की है... मुझे इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि पूंजी की दृष्टि से कंपनी के व्यापार के लिए कोई स्थायी लाभ की मांग की जा रही थी, और न ही यह सुझाव दिया गया था कि वास्तव में ऐसा कोई लाभ प्राप्त किया जाएगा।

12) श्री शर्मा ने स्कैनमेल एंड नेफ्यू लिमिटेड बनाम रोल्स (7) पर भी रिलायंस को रखा है, जहां सर वाइल्डफ्रिड ग्रीन एम. आर. ने निश्चित और परिसंचारी पूंजी से किए जा रहे व्यय के दृष्टिकोण से परीक्षण

पर चर्चा की है, एक ऐसी परीक्षा जो सार्वभौमिक अनुप्रयोग की नहीं है और विशेष रूप से मामले के लिए उपयुक्त नहीं है।

13) लॉर्ड रैडक्लिफ ने कर आयुक्त बनाम नोहंगा समेकित कॉपर माइंस लिमिटेड (8) में प्रिवी काउंसिल के फैसले में 'स्थायी लाभ' या 'पूंजी संरचना' वाक्यांशों को निश्चित के बजाय विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक बताया है। जैसा कि 'द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम-टैक्स' पर कंगा की टिप्पणी में कहा गया है-छठा संस्करण (खंड। ।)-पृष्ठ 438 पर –

'स्थायी' और 'स्थायी' शब्द केवल सापेक्ष शब्द हैं और शाश्वत या शाश्वत का पर्याय नहीं हैं। वे केवल यह इंगित करते हैं कि अर्जित संपत्ति या अधिकार में पर्याप्त स्थायित्व होना चाहिए ताकि इसे पूंजीगत संपत्ति के रूप में माना जा सके। स्थायित्व या स्थायित्व की वह डिग्री क्या होनी चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।"

मामले में किया गया व्यय किसी भी मानक द्वारा स्थायित्व की कसौटी को पार कर जाएगा ताकि इसे निर्धारिती-कंपनी के स्थायी लाभ के लिए किए गए व्यय के रूप में स्थान दिया जा सके।

14) दो अन्य अंग्रेजी मामलों का भी उल्लेख किया जा सकता है, हालाँकि इन्हें बार में उद्धृत नहीं किया गया था। "व्यापार के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित और व्यय किया गया धन" शब्द, जो हमारे कानून [धारा 10 (2) (xv)] में प्रयुक्त भाषा से भिन्न नहीं हैं, का अर्थ इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारिती के व्यापार के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और असाधारण रूप से निर्धारित या व्यय के रूप में किया गया है। लॉर्ड डेवी ने पृष्ठ 453 पर स्ट्रॉन्ग एंड कंपनी ऑफ रॉम्से लिमिटेड बनाम वुडी-फील्ड (9) में, निर्धारिती पर चिमनी गिरने के लिए लगाए गए हर्जाने के संबंध में, ऐसे व्यय होने के लिए कहा, जिनकी कटौती नहीं की जा सकती थी और इस प्रकार अवलोकन किया जा सकता था –
"मेरा मानना है कि इन नुकसानों का भुगतान 'व्यापार के उद्देश्य' के लिए नहीं किया गया था। मुझे लगता है कि इन शब्दों का अर्थ किसी व्यक्ति को व्यापार आदि में आगे बढ़ने और लाभ कमाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से है। यह पर्याप्त नहीं है कि संवितरण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, या इससे उत्पन्न होता है। या व्यापार से जुड़ा हुआ है, या व्यापार के लाभ से बना है। इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया जाना चाहिए।"

लॉर्ड लॉरबर्न, L.C. ने इसी मामले में कहा कि निर्धारिती द्वारा किया गया नुकसान वास्तव में उसके व्यापार के लिए आकस्मिक नहीं था और इसलिए इसकी कटौती नहीं की जा सकती थी। कटौती योग्य नुकसान ऐसे होने चाहिए जो इस अर्थ में जुड़े हों कि वे वास्तव में व्यापार के लिए ही आकस्मिक हैं।

15) हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक अन्य निर्णय में स्मिथ्स पोटेटो एस्टेट्स लिमिटेड बनाम बॉयलैंड (कर निरीक्षक) (10) लॉर्ड पोर्टर, आयकर अधिकारियों के समक्ष निर्धारण की राशि को चुनौती देने के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में बहुमत के लिए बोलते हुए, पृष्ठ 521 और 523 में कहा गया है-
"ऐसा व्यय सीधे कर उद्देश्यों के लिए किया जाता है और कुछ और नहीं, हालांकि यह अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय के मालिकों को वितरण के लिए उपलब्ध राशि और आरक्षित करने के लिए उचित दोनों को प्रभावित कर सकता है।"

"आय-कर या अतिरिक्त लाभ कर की सही राशि निर्धारित करने के लिए ऐसा व्यय, जैसा भी मामला हो, न कि लाभ अर्जित करने के लिए, भले ही उस वाक्यांश को व्यापक महत्व दिया जाए, राजस्व व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

16) समान शब्द जो हमारे समक्ष मामले में निर्माण के लिए आते हैं, एक व्यय के संबंध में हैं, जो कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, "ऐसे व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और निर्णायक रूप से खर्च किया जाना चाहिए था।

17) श्री शर्मा ने तब इस विषय पर भारतीय मामलों के एक समूह की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो एंग्लो-फारसी ऑयल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम आय-कर आयुक्त (11) से शुरू होता है, जिसमें यह रैंकिन, सी. जे. और बकलैंड, जे. द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि कंपनी द्वारा एजेंसी के नुकसान के मुआवजे के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान किया गया था, जहां कंपनी ने राजस्व खाते में प्रभार्य कमीशन के भविष्य के वार्षिक भुगतान से खुद को मुक्त कर दिया था, ठीक से कटौती योग्य है क्योंकि ऐसे लाभ या लाभ अर्जित करने के उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय। पीठ ने यह इंगित किया कि कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यय खाते के वर्ष में लाभ या लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाना आवश्यक नहीं है। कॉस्टेलो और लॉर्ड विलियम्स, जज, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड (12) द्वारा एक अन्य पीठ के फैसले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती कंपनी द्वारा एजेंसी व्यवसाय के कम के लिए मुआवजे के रूप में प्रबंध एजेंसी को पांच साल की अवधि के लिए 500 रुपये प्रति माह की किश्तों के रूप में भुगतान किए गए 30,000 रुपये की राशि अधिनियम की धारा 10 (2) (ix) के तहत राजस्व व्यय की प्रकृति में थी क्योंकि निर्धारिती "सद्भावना की प्रकृति में किसी नए व्यवसाय का पोषण या संरक्षण या कुछ भी खरीद नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल अपने उपक्रम और भविष्य के संचालन के लिए सुविधाओं के लिए लाभ प्राप्त कर रहे थे और क्योंकि भुगतान परिसंचारी पूंजी से किया गया था और इसके परिणामस्वरूप कोई नई संपत्ति या निर्धारिती की निश्चित पूंजी में वृद्धि नहीं हुई थी। हालांकि पीठ ने एथर्टन के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले का उल्लेख किया (5) ऐसा लगता है कि निर्णय डेल के मामले के अधिकार पर आधारित है (6).

18) 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई स्थिति के बारे में विद्वान वकील द्वारा संदर्भित मामलों का अगला सेट। यूरोपीय लोगों के स्वामित्व वाली या विशेष रूप से यूरोपीय लोगों के स्वामित्व वाली कंपनियों को व्यावहारिकता के व्यावहारिक विचारों के लिए भारतीय हाथों में सौंप दिया गया, और कंपनियों के सेवानिवृत्त होने वाले प्रबंध निदेशकों या प्रबंध एजेंसियों को मुआवजा दिया जाना था। इन सभी मामलों में, यह माना गया था कि इस तरह के भुगतान राजस्व व्यय की प्रकृति के थे। पी. ओर एंड संस बनाम आय-कर आयुक्त। मद्रास (13) निर्धारिती ने रु। अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के अधीन अनुज्ञेय कटौती के रूप में 1,25,000 का भुगतान प्रबंध अभिकरण करार को समाप्त करने के लिए प्रतिकर के रूप में किया गया। इस प्रकार भुगतान की गई राशि 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए प्रबंध एजेंटों को दिए गए कमीशन का प्रतिनिधित्व करती है। 1948 में। राजगोपालन और बालकृष्ण अय्यर, जे. जे. द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि रु। 1,25,000 कंपनी के लिए प्रबंध एजेंसी और उसके परिचर आवर्ती वार्षिक दायित्व की समाप्ति को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था और किसी भी पूंजीगत संपत्ति में लाने का इरादा नहीं था, न ही यह किसी भी पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण में परिणाम था और नहीं था। इसलिए, पूंजीगत व्यय की एक वस्तु। पीठ ने आगे कहा कि व्यावसायिक समीचीनता की कसौटी पर विचार करते हुए यह राशि पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारिती कंपनी के व्यवसाय के लिए खर्च की गई थी। इसी प्रकार एफ. ई. डर्टशॉ लिमिटेड बनाम आय-कर आयुक्त (14) में निर्धारिती कंपनी ने रु। (ख) निदेशक के समनुदेशन को समाप्त करने के लिए प्रतिकर के रूप में 1,00,000 और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस प्रकार संदत्त राशि युक्तियुक्त होने के कारण लाभ अर्जित करने

के प्रयोजन के लिए थी. एस. टी. देसाई और जे. जे. के. टी. देसाई ने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले को वाणिज्यिक व्यापार और वाणिज्यिक समीचीनता के सिद्धांतों के आलोक में देखा जाना चाहिए। व्यय निर्धारिती के व्यवसाय के लिए होना चाहिए न कि कुछ ऐसा जो व्यवसाय को प्रभावित करता हो।

19) ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आय-कर आयुक्त (15) वाले मामले में ताम्बे और वी. एस. देसाई, न्यायमूर्ति द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रबंध एजेंसी कमीशन के भुगतान के मामले में अपने आवर्ती दायित्व से छुटकारा पाने और/या अपने निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधन को संभालने की दृष्टि से प्रबंधित कंपनी द्वारा अपनी अवधि की समाप्ति से पहले प्रबंध एजेंसी समझौते की समाप्ति अप्रत्यक्ष रूप से अपने व्यवसाय के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में एक लेनदेन होगा। यह पाया गया कि व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया था। हालाँकि, अपील में, इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी बनाम ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड (2) में उलट दिया गया था और मामले को मामले के पूर्ण विचार के लिए न्यायाधिकरण को भेज दिया गया था।

20) अंत में, आयकर आयुक्त बनाम टर्नर मॉरिसन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (16) बनर्जी और के. एल. रॉय के मामले में। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में जहां निर्धारिती कंपनी ने अपने कुछ वरिष्ठ यूरोपीय कर्मचारियों की सेवाओं को उनके साथ अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले समाप्त कर दिया था, प्रशासनिक लागत को कम करने और कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति में तेजी लाने और उन्हें एकमुश्त मुआवजे का भुगतान करने की दृष्टि से समाप्त हो गया था, व्यय की कटौती की जानी चाहिए क्योंकि यह निर्धारिती के व्यवसाय के हित में था और पूरी तरह से और विशेष रूप से अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया था।

21) अब हम इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों पर आते हैं। असम में बंगाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (17) श्री न्यायमूर्ति भगवती ने पूंजी और राजस्व व्यय के बीच सीमांकन की रेखा पर चर्चा करते हुए पूरे मामले के कानून पर चर्चा की है। उस मामले में निर्धारिती कंपनी ने 1 नवंबर, 1938 से बीस साल की अवधि के लिए सीमेंट के निर्माण के उद्देश्य से खासी और जयंतिया पहाड़ियों में चूना पत्थर की खदानों के पट्टे का असम सरकार से अधिग्रहण किया था। पट्टे की भारी और पर्याप्त राशि पहले पांच वर्षों में देय हो गई, जिसकी राशि रु। 40, 000। निर्धारिती कंपनी ने अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के उपबंधों के अधीन लेखा वर्ष 1944-45 और 1945-46 में इस राशि की कटौती करना चाहा।

पट्टे के पहले पांच वर्षों में भुगतान किया गया था और पट्टे की शेष अवधि के लिए निर्धारिती कंपनी को ये भुगतान नहीं करना पड़ा था। उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस प्रकार भुगतान की गई राशि अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के तहत राजस्व व्यय के रूप में कटौती योग्य नहीं थी और इसकी पुष्टि उच्चतम न्यायालय में की गई थी। श्री न्यायमूर्ति भगवती ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए पृष्ठ 47 पर टिप्पणी की –

"जिन 5 वर्षों की अवधि में भुगतान किया गया था, उससे अधिग्रहण की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी यह एक स्थायी प्रकृति के लाभ का अधिग्रहण था जो पट्टा की पूरी अवधि के लिए पूरे व्यवसाय के लाभ के लिए सुनिश्चित करता था जब तक कि पट्टेदार द्वारा खंड के अंतिम भाग में निर्धारित सूचना द्वारा समाप्त नहीं किया जाता था। यह फिर से पूरे व्यवसाय के लिए एक स्थायी प्रकृति की संपत्ति या लाभ का अधिग्रहण था।

उच्चतम न्यायालय की राय में, कंपनी ने इस आवर्ती भुगतान को ध्यान में रखते हुए जो संपत्ति अर्जित की थी, वह स्थायी लाभ की पूंजीगत संपत्ति की प्रकृति की थी। अंग्रेजी मामलों में विभिन्न परीक्षण, जिनके लिए संदर्भ दिया गया है, इस निर्णय में पूरी तरह से चर्चा की गई थी और एथर्टन के मामले (5) में लॉर्ड केव का परीक्षण सबसे उपयुक्त पाया गया था।

22) उच्चतम न्यायालय का एक अन्य निर्णय जिस पर आयकर न्यायाधिकरण के निर्णय द्वारा निर्भरता रखी जाती है, वह है गोदरेज एंड कंपनी बनाम आयकर आयुक्त (18). यहां, अक्टूबर, 1928 के एक समझौते के तहत गोदरेज साबुन लिमिटेड के प्रबंध एजेंट के रूप में निर्धारिती कंपनी को असामान्य रूप से बीस प्रतिशत का एक बड़ा कमीशन दिया जा रहा था, जिसे दिसंबर, 1933 के एक अन्य समझौते द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जैसे-जैसे प्रबंधित कंपनी का व्यवसाय विकसित और विस्तारित हुआ, उसके निदेशकों और शेयरधारकों ने पाया कि प्रबंध एजेंटों की निर्धारिती फर्म को बहुत अधिक दर पर भुगतान किया जा रहा था और इस समझौते के संशोधन के लिए बातचीत शुरू की गई थी। इस संशोधित समझौते के अनुसरण में, प्रबंध एजेंसी के समझौते में निहित पारिश्रमिक के रूप में प्रबंधित कंपनी को भारी अवधि से मुक्त करने के लिए निर्धारिती फर्म को मुआवजे के रूप में 7,50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। यह निर्धारित किया जाना था कि क्या प्रबंध अभिकर्ताओं द्वारा 7,50,000 रुपये की प्राप्ति पूंजी या राजस्व प्राप्ति की प्रकृति में थी। मुख्य न्यायाधीश दास ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए पृष्ठ 385 पर इस प्रकार टिप्पणी की –

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि 7,50,000 रुपये की इस राशि का भुगतान करके th.at प्रबंधित कंपनी ने मूल समझौते द्वारा कवर की गई प्रबंध एजेंसी की शेष अवधि के लिए निर्धारिती फर्म से अपने लिए एक रिलीज सुरक्षित कर ली है। प्रथम दृष्टया, 17 वर्षों से अधिक के लिए उच्च पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए दायित्व से यह छूट प्रबंधित कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय के लाभ के लिए प्राप्त एक लाभ होना चाहिए और इस प्रकार प्रबंधित कंपनी द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा को पूंजी परिव्यय के माध्यम से स्थायी मूल्य की संपत्ति का अधिग्रहण माना जा सकता है, जो कि विसकाउंट केव, एल. सी. द्वारा एथर्टन बनाम ब्रिटिश इंसल्टेड एंड हेल्सबी केबल्स लिमिटेड में निर्धारित परीक्षण के अनुसार पूंजीगत व्यय होगाः जिसका उल्लेख असम-बंगाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त में इस न्यायालय के फैसले में किया गया है। निष्कर्ष में विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने अधिकारियों की चर्चा के बाद इस प्रकार टिप्पणी की -

उन निर्णयों के आलोक में 7,50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया और प्राप्त किया गया, जो उच्च पारिश्रमिक और कम पारिश्रमिक के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए नहीं था, बल्कि वास्तव में कंपनी को पारिश्रमिक के रूप में कठिन शर्तों से मुक्त करने के लिए मुआवजे के रूप में भुगतान और प्राप्त किया गया था। दूसरे शब्दों में, जहां तक प्रबंधित कंपनी का संबंध था, इसका भुगतान प्रबंध एजेंसी के शेष कार्यकाल के लिए निर्धारिती फर्म को उच्च पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए दायित्व से प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसलिए, एक पूंजीगत व्यय और जहां तक निर्धारिती फर्म का संबंध था, इसे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के अपने अधिकारों को जारी करने के कारण प्रबंधन एजेंसी को गिरावट या क्षति के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्त किया गया था और इसलिए, ऊपर उल्लिखित पहले के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों के भीतर एक पूंजी रसीद।

यह सच है कि गोदरेज के मामले में निर्धारिती फर्म (18) 7,50,000 रुपये का प्राप्तकर्ता था और यह पाया गया कि उसके हाथों में यह आयकर के लिए आकलन योग्य राजस्व रसीद थी। श्री शर्मा ने यह स्वीकार करते हुए कि प्रबंधित कंपनी के मामले में इस व्यय की प्रकृति के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायाधीश का अवलोकन, उनके द्वारा तर्कित परिणाम के विरुद्ध है। इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि राय

की अभिव्यक्ति केवल आज्ञाकारी है, सर्वोच्च न्यायालय प्रबंधित कंपनी के मूल्यांकन से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। हम विद्वान वकील के इस सुझाव को स्वीकार करने का अपना तरीका नहीं देखते हैं। एथर्टन के मामले (5) में निर्धारित परीक्षण सहित पूरे मामले के कानून पर पूरी तरह से चर्चा की गई है और असम बंगाल सीमेंट कंपनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा की गई है (17). यह निष्कर्ष स्पष्ट भाषा में निकाला गया है कि प्रबंधित कंपनी द्वारा प्रबंध कंपनी को 7,50,000 रुपये का भुगतान पूंजीगत व्यय के रूप में किया गया था। यह ऐसा निष्कर्ष नहीं था जो मामले के तथ्यों से असंबंधित था। प्रबंध अभिकर्ताओं की प्राप्तकर्ता फर्म ने पूंजी या राजस्व रसीद के रूप में 7,50,000 रुपये प्राप्त किए थे या नहीं, यह निर्धारित करने में उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्यों ने भी प्रबंधित कंपनी के हाथों में व्यय की प्रकृति निर्धारित की। उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि 7,50,000 रुपये की राशि प्रबंधित कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय का प्रतिनिधित्व करती है, यह निर्धारिती फर्म के हाथों में पूंजी रसीद होनी चाहिए। पूंजीगत राशियों और राजस्व मदों की आंतरिक विशेषताएं क्रमशः प्राप्तियों के लिए और व्यय के लिए अनिवार्य रूप से समान हैं। इस तर्क को खारिज कर दिया गया था और यह स्पष्ट है कि प्रबंधित कंपनी के हाथों में खर्च की प्रकृति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां आज्ञाकारी की प्रकृति में नहीं थीं, बल्कि उनके प्रभुओं के सामने उठाए गए तर्कों से सीधा संबंध रखती थीं।

23) राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के संबंध में रल्ली एस्टेट्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (19) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय में कुछ इसी तरह का तर्क दिया गया था। बोर्ड का निर्णय देते हुए, लॉर्ड डेनिंग को पृष्ठ 335 पर इन शब्दों के साथ विवाद को दूर करने में कोई कठिनाई नहीं हुई

"भुगतान जो प्राप्तकर्ता के हाथों में आय रसीदें हैं, जरूरी नहीं कि भुगतानकर्ता के हाथों में राजस्व व्यय हों।"और बोर्ड तदनुसार इस प्रश्न से निपटने के लिए आगे बढ़ा कि क्या विचाराधीन भुगतान पूरी तरह से और विशेष रूप से दाता की आय के उत्पादन में किए गए खर्च थे।

24) निर्धारिती के मामले के समर्थन में उद्धृत अधिकारी, मोटे तौर पर बोलते हुए, अस्थायी समाधानों या मतूराम बनाम किशन द्वारा किए गए निर्णयों से संबंधित थे। प्रसाद और अन्य, (मेहर सिंह, C.J.) इस समय के आर्थिक या प्रबंधकीय संकट के दबाव में और भविष्य की आर्थिक समृद्धि की नींव या आधार रखने के लिए नियोजित नीति के माध्यम से नहीं। इन सभी मामलों में निर्धारिती को, निस्संदेह, तत्काल और महत्वपूर्ण हित के मामलों के रूप में दूरगामी महत्व के निर्णयों पर पहुंचना था। वर्तमान मामले में हम जो पाते हैं वह यह है कि निर्धारिती कंपनी को किसी भी तत्काल या वर्तमान खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था, न ही प्रबंध एजेंसी समझौते को समाप्त करने के लिए निदेशक मंडल को किसी भी वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ा और न ही इस पाठ्यक्रम को अपनाने से किसी भी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। स्पष्ट रूप से, निदेशकों ने प्रबंध अभिकर्ताओं के समेकित दावे को जोड़ दिया, जिनकी सेवाओं को स्पष्ट रूप से बिना किसी कारण के समाप्त कर दिया गया था और इस उद्देश्य के लिए 6,00,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, निस्संदेह, निर्धारिती कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से एक स्थायी लाभ हुआ। यह देखते हुए कि जो समझौता समाप्त किया जा रहा था वह समनुदेश्य था और डालमिया जैन एंड कंपनी के स्थान पर सफल होने के लिए कोई प्रबंध अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया गया था, एक स्थायी प्रकृति का एक स्पष्ट लाभ अस्तित्व में लाया गया था, एक स्थायी प्रकृति का लाभ, निर्धारिती कंपनी के लिए एक भौतिक या अचल संपत्ति से अप्रभेद्य लाभ। मामले के इस दृष्टिकोण में हम सोचते हैं कि निर्धारिती का तर्क विफल होना चाहिए और हम तदनुसार राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ प्रश्न का उत्तर देंगे। इन परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

आर. एस. नरूला, जे. -मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फरीदाबाद, हरियाणा